

[2023] 3 एस. सी. आर. 552

[2023] 3 एस सी आर।

श्री राकेश रमन

बनाम

श्रीमती कविता

(सिविल अपील सं. 2013 की 2012) अप्रैल 26, 2023

[न्यायमूर्तिगण सुधांशु धूलिया और जे. बी. पारदीवाला]

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955: धारा 13 (1) (आई. ए.) और (आई. बी.)-तलाक-क्रूरता और त्याग के आधार-पक्षों के बीच वैवाहिक कलह-पति द्वारा इस आधार पर विवाह भंग करने की याचिका कि पत्नी ने उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया और उसे छोड़ दिया, कि पक्षों के बीच कोई सह-वास नहीं था, और पत्नी ने उसके खिलाफ कई झूठे और तुच्छ आपराधिक मामले दायर किए थे-निचली न्यायालय ने तलाक की डिक्री पारित करते हुए कहा कि पत्नी ने पति को छोड़ दिया था और उसके खिलाफ क्रूर व्यवहार किया था-हालांकि, उच्च न्यायालय ने आदेश अपास्त कर दिया-अपील पर, कहा: दोनों पक्षों की ओर से क्रूरता और त्याग के कड़े आरोप हैं, वैवाहिक संबंध अपरिवर्तनीय रूप से टूट गए हैं, 25 साल का लंबा अलगाव है, सहवास की अनुपस्थिति है, विवाह से बाहर कोई बच्चा नहीं है, पक्षों के बीच कई न्यायालयी मामले हैं-न्यायालयों द्वारा सुलह के लिए बार-बार प्रयास विफल रहे हैं-वैवाहिक संबंध जो पिछले कुछ वर्षों में केवल अधिक कड़वा और कटु हो गया है, दोनों पक्षों पर क्रूरता फैलाने के अलावा कुछ नहीं करता है-इस टूटी हुई शादी के अग्रभाग को जीवित रखना दोनों पक्षों के साथ अन्याय करना होगा-विवाह का अपरिवर्तनीय रूप से टूटना क्रूरता को दर्शाता है, इस प्रकार, विवाह के विघटन के लिए एक आधार है। 13(1)(ia)-उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय को अपास्त करना दिया जाता है और तलाक की डिक्री दी जाती है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** पति और पत्नी पिछले **25** वर्षों से अलग रह रहे हैं। विवाह से बाहर कोई संतान नहीं है। दोनों पक्षों की ओर से क्रूरता और पलायन के तीखे आरोप हैं और पिछले **25** से अधिक वर्षों में दोनों के बीच कई मुकदमे हैं। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच यह कड़वा संबंध, जिसने पिछले **25** वर्षों से शांति का कोई क्षण नहीं देखा है, केवल कागज पर एक वैवाहिक संबंध है। तथ्य यह है कि इस रिश्ते ने अपरिवर्तनीय रूप से बहुत पहले तोड़ दिया है। विचार किए जाने वाला एक अन्य पहलू यह तथ्य है कि पिछले **25** वर्षों से अपीलार्थी और प्रत्यर्थी अलग रह रहे हैं, और साथ नहीं रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है। वास्तव में दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है और जैसा कि विधि आयोग ने अपनी **71** वीं

रिपोर्ट में इस तरह के विवाह के बारे में कहा है, जो एक ऐसा विवाह है जो वास्तव में टूट गया है, और केवल कानून द्वारा न्यायिक मान्यता की आवश्यकता है। विधि आयोग ने अपनी **217** वीं रिपोर्ट में भी यही बात दोहराई थी। [पैरा **10,12**] [558-ए-बी, ई-एफ]

1.2 उच्च न्यायालय द्वारा यह विचार कि पत्नी द्वारा केवल आपराधिक मामले दायर करना क्रूरता नहीं है, क्योंकि यह भी देखा जाना चाहिए कि किन परिस्थितियों में मामले दायर किए गए थे, एक निष्कर्ष है जिसे पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, वास्तव में कानून के एक शुद्ध प्रस्ताव के रूप में यह सही हो सकता है, लेकिन फिर मामले के पूरे तथ्यों की बारीकी से जांच की जानी चाहिए। जब उन तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है जो वे मौजूद हैं, तो इस विवाह को जारी रखने का मतलब क्रूरता जारी रखना होगा, जो प्रत्येक एक दूसरे को देता है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह का अपरिवर्तनीय टूटना विवाह के विघटन का आधार नहीं हो सकता है, लेकिन क्रूरता है। विवाह को तलाक की डिक्री द्वारा भंग किया जा सकता है, अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर कि जब दूसरे पक्ष ने "विवाह के अनुष्ठान के बाद याची के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है"। एक वैवाहिक संबंध जो पिछले कुछ वर्षों में और अधिक कड़वा और कटु हो गया है, दोनों पक्षों पर क्रूरता फैलाने के अलावा कुछ नहीं करता है। इस टूटी हुई शादी के अग्रभाग को जीवित रखना दोनों पक्षों के साथ अन्याय करना होगा। एक विवाह जो अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है, दोनों पक्षों के लिए क्रूरता का संकेत देता है, क्योंकि इस तरह के रिश्ते में प्रत्येक पक्ष दूसरे के साथ क्रूरता का व्यवहार कर रहा है। इसलिए यह धारा **13 (1) (आई. ए.)** के तहत विवाह के विघटन का आधार है। [पैरा **16**] [560-डी-जी]

1.3 वैवाहिक बंधन पूरी तरह से टूट गया है और सुधार से परे है। यह संबंध समाप्त होना चाहिए क्योंकि इसकी निरंतरता दोनों पक्षों में क्रूरता का कारण बन रही है। लंबे समय तक अलग रहने और सहवास की अनुपस्थिति और सभी सार्थक बंधनों के पूरी तरह से टूटने और दोनों के बीच मौजूदा कड़वाहट को **1955** के अधिनियम की धारा **13 (1) (आई. ए.)** के तहत क्रूरता के रूप में देखा जाना चाहिए। इसलिए, किसी दिए गए मामले में, जहां वैवाहिक संबंध अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है, जहां पक्षों के बीच कई न्यायालयी मामलों के साथ लंबे समय तक अलगाव और सहवास की अनुपस्थिति (जैसा कि पिछले **25** वर्षों के तत्काल मामले में) है; तो इस तरह के 'विवाह' को जारी रखने का मतलब केवल क्रूरता को मंजूरी देना होगा जो प्रत्येक दूसरे को दे रहा है। इस विवाह का विघटन केवल दोनों पक्षों को प्रभावित करेगा क्योंकि विवाह से कोई संतान नहीं है। [पैरा **18**] [562-सी-ई]

1.4 इन परिस्थितियों में, निचली विचारण न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा जाता है, हालांकि विभिन्न आधारों के लिए दिया जाता है और उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त करना दिया जाता है और अपीलार्थी/पति को तलाक की डिक्री दी जाती है। उनकी शादी टूट जाएगी। हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी/पति जीवन बीमा निगम में एक कर्मचारी है, वर्तमान वेतन रुपये से अधिक है—(एक लाख रुपये) प्रति माह, यह उचित और उचित माना जाता है कि वह प्रतिवादी/पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप

मे**Rs.30,00,000/-** (तीस लाख रुपये) की राशि देता है।[पारस **19,20**] **[562-एफ-एच]**

समर घोष बनाम जया घोष **(2007) 4 एससीसी 511-आश्रित**

नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली **(2006) 4 एससीसी 558;** के. श्रीनिवास राव बनाम डीए। दीपा **(2013) 5 एस. सी. सी. 226;** आर. श्रीनिवास कुमार बनाम आर. शमिता **(2019) 9 एस. सी. सी. 409;** मुनीश कक्कड़ बनाम निधि कक्कड़ **(2020) 14 एस. सी. सी. 657;** नेहा त्यागी बनाम लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक त्यागी **(2022)**

3 एस. सी. सी. 86-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

(2006) 4 एस. सी. सी. 558	संदर्भित किया गया है	पैरा 11
(2013) 5 एससीसी 226	संदर्भित किया गया है	पैरा 11
(2019) 9 एस. सी. सी. 409	संदर्भित किया गया है	पैरा 13
(2020) 14 एस. सी. सी. 657	संदर्भित किया गया है	पैरा 13
(2022) 3 एस. सी. सी. 86	संदर्भित किया गया है	पैरा 13
(2007) 4 एस. सी. सी. 511	पर भरोसा किया गया	पैरा 16 ए

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार-2013 की सिविल अपील सं. 2012।

2009 के एम. ए. टी. ए. पी. सं. 52 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 08.04.2011 के निर्णय और आदेश से।

एस. के. रूंगटा, वरिष्ठ अधिवक्ता, अरविंद कुमार गुप्ता, नरेश दक्ष, अभिसुमत गुप्ता, रंजन भोरिया, सी. प्रकाश, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।एस. के. भल्ला, एस. आर. सेतिया, सुश्री अंजलि तिवारी, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुधांशु धूलिया द्वारा दिया गया था।

1. यह अपील हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 13 के तहत अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (उत्तर), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली के न्यायालय में शुरू की गई तलाक की कार्यवाही से उत्पन्न होती है।उनके मुकदमे का फैसला सुनाया गया और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (उत्तर) के आदेश दिनांक 02.05.2009 द्वारा शादी को भंग कर दिया गया।इसके बाद प्रतिवादी/पत्नी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की, जिसने विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त करना दिया और पति की याचिका को खारिज कर दिया।उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी/पति

ने इस न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें 26.02.2013 पर अनुमति दी गई थी।

2. अपीलार्थी और प्रत्यर्थी की शादी दिल्ली में हिंदू रीति-रिवाजों और रीति-रिवाजों के तहत 16.04.1994 पर हुई थी। अफसोस की बात है कि वैवाहिक कलह को उनके वैवाहिक जीवन में स्थापित होने में अधिक समय नहीं लगा। अपीलार्थी का मामला यह है कि उसकी पत्नी अपने छोटे से घर में खुश नहीं थी, और उसने उसके खिलाफ अपमानजनक, यहां तक कि अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। यह भी आरोप लगाया गया है कि सितंबर, 1994 में, उसने अपने पति को बिना किसी पूर्व सूचना के अपनी गर्भावस्था को समाप्त कर दिया (इस आरोप से पत्नी ने इनकार किया था और उसके खिलाफ कभी भी साबित नहीं किया जा सका)। सितंबर 1994 में उन्होंने फिर से अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया, लेकिन शुभचिंतकों और रिश्तेदारों द्वारा किए गए प्रयासों के कारण, वे मार्च 1995 से एक साथ रहने लगे। यह फिर से लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि 16.02.1998 पर उसने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया, और 16/17.02.1998 पर स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मार्च 1998 में, वह इस शर्त पर अपने पति के साथ शामिल होने के लिए सहमत हो गई कि अपीलार्थी एक और आवास लेगा और परिणामस्वरूप अप्रैल 1998 में एक और घर किराए पर ले लिया गया, और दोनों नए घर में एक साथ रहने लगे। लेकिन फिर, 24.08.1998 पर, अपीलार्थी का आरोप है कि उसे उसकी पत्नी और उसके भाई ने पीटा था। 29.11.1998 पर, उन्हें पूरी रात अपने घर से बाहर रखा गया था। आई. डी. 1 पर उसने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया और अपीलार्थी और उसके भाई के खिलाफ आनंद पर्वत पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए/406 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई। अपीलार्थी और उसके भाई को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था, जब वे एक विवाह समारोह में भाग ले रहे थे, और यह उसके 15 से 20 दोस्तों की उपस्थिति में किया गया था। बाद में दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया, हालांकि पत्नी मामले पर कायम रही और यहां तक कि उनकी जमानत रद्द करने के लिए एक आवेदन भी दायर किया। इसके बाद पत्नी ने अपीलार्थी/पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आईपीसी की धारा 34 के सहपठित धारा 323 और 324 के तहत शिकायत दर्ज कराई, हालांकि बाद में उन्हें मामले से बरी कर दिया गया। प्रत्यर्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 150 सहपठित धारा 107 के तहत अपीलार्थी के खिलाफ कार्यवाही भी शुरू की। इसके बाद उन्होंने अपने भरण-पोषण के लिए हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम, 1956 की धारा 18 के तहत एक याचिका दायर की।

3. अपनी पत्नी द्वारा छोड़े जाने और उन पर लगाए गए कई मुकदमों के बोझ के कारण, अपीलार्थी ने वैवाहिक संबंधों को समाप्त करने का निर्णय लिया। इस प्रकार उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (आई. ए.) और (आई. बी.) के तहत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, उत्तरी दिल्ली के समक्ष अन्य बातों के साथ-साथ तथ्यों पर विवाह विच्छेद के लिए अपनी याचिका दायर की, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में वर्णित है।

4. प्रत्यर्थी इस बात से इनकार करता है कि उसने कभी भी अपने पति को 'छोड़ दिया' या उस पर कोई क्रूरता की। उसके वकील ने कहा कि उसने केवल कानून के तहत उसके लिए उपलब्ध कानूनी रास्तों का सहारा लिया। वह आरोप लगाती है कि उसके गहने जो उसका 'स्त्रीधन' थे, उन्हें ले जाया गया और कभी वापस नहीं किया गया, और कैसे उसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए और 406 के तहत अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए मजबूर किया गया। यह उनका मामला भी था कि उन्होंने सुलह के लिए हर संभव प्रयास किया था, लेकिन अपीलार्थी के असहयोग के कारण, मध्यस्थता और समाधान की दिशा में सभी प्रयास विफल रहे। उसने इस बात से इनकार किया है कि उसने अपनी गर्भावस्था को समाप्त कर दिया था।

5. 15.10.2003 पर परिवार न्यायालय ने क्रूरता और पलायन पर मुद्दे बनाए। विचारण न्यायालय ने क्रूरता के साथ-साथ पति के पक्ष में त्याग पर निष्कर्ष दिए और विवाह के विघटन के लिए एक डिक्री पारित की गई।

6. उच्च न्यायालय अपील में इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि केवल यह तथ्य कि प्रत्यर्थी ने अपने पति को अपने घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी 29.11.1998, यह साबित नहीं करेगा कि स्थायी रूप से सहवास को समाप्त करने का उसका इरादा था और इसलिए त्याग पर विवाह के विघटन का आधार नहीं बनाया गया था। जहाँ तक आई. पी. सी. की धारा 323, 324 और 498 ए के तहत विभिन्न शिकायतें दर्ज करने का संबंध है, उच्च न्यायालय का विचार था कि केवल ऐसी शिकायतें दर्ज करना या उनके बरी होने का परिणाम क्रूरता नहीं होगी, क्योंकि पत्नी केवल कानून के तहत उसके लिए उपलब्ध अपने विकल्पों का उपयोग कर रही थी। इसके अलावा, यह भी देखना होगा कि ये शिकायतें किन परिस्थितियों में दर्ज की गईं। 7. हमने अपीलार्थी/पति के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. के. रूंगटा और प्रतिवादी/पत्नी के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री एस. के. भल्ला को विस्तार से सुना है और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन है।

8. यह मामला पारिवारिक न्यायालय से उच्च न्यायालय और अब अंत में इस न्यायालय तक गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय 08.04.2011 का है, जो बारह साल पुराना है। हमें उन सभी तथ्यों को ध्यान में रखना होगा जो अभी हमारे सामने हैं। हमारे दिमाग में जिन तथ्यों को हमें ध्यान में रखना चाहिए वे हैं: (i) कि "जोड़ा" अब पिछले लगभग 25 वर्षों से अलग रह रहा है, और इन सभी वर्षों में उनके बीच कोई सहवास नहीं रहा है। (ii) कि विवाह से कोई संतान नहीं है, और दंपति मुश्किल से 4 साल तक पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहे। (iii) अदालतों द्वारा सुलह या समझौते के लिए बार-बार किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप विफलता हुई है।

9. प्रारंभिक चरण में विचारण न्यायालय ने पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजा था, जो सफल नहीं हुआ। इस न्यायालय ने दोनों को मध्यस्थता के लिए भी भेजा था, जो विफल रहा। मामला फिर से लोक अदालत में निपटारे के लिए भेजा गया था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 11.04.2015 पर, इस न्यायालय ने फिर से पक्षों से एक साथ रहने की संभावनाओं का पता लगाने का अनुरोध किया, लेकिन कुछ भी अमल में नहीं आया। फिर 09.05.2015 पर, इस

न्यायालय ने पक्षों को कुछ आपसी समझौते पर आने के लिए कहा, लेकिन व्यर्थ। दूसरे शब्दों में, एक समझौते या समझौते की दिशा में न्यायालय और मध्यस्थों के हर एक प्रयास ने एक अंधा रास्ता बना दिया है। अब भी, पक्षों को औपचारिक सुनवाई देने से पहले हमने पक्षों से वर्तमान स्थिति को इकट्ठा करने की कोशिश की। अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी समझौते या समझौते के लिए कोई जगह नहीं है और वह अनुरोध करता है कि इस मामले में उसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाए, जबकि प्रत्यर्थी के वकील ने इस न्यायालय को अवगत कराया कि प्रत्यर्थी उसकी शादी को बचाना चाहता है और वह एक बार फिर मध्यस्थता के लिए प्रार्थना करता है। उन्होंने यह भी कहा कि तलाक का कोई आधार नहीं बनाया गया है और दिल्ली उच्च न्यायालय के सुविचारित फैसले को बरकरार रखा जाना चाहिए।

10. पति और पत्नी, जो हमारे समक्ष हैं, पिछले 25 वर्षों से अलग रह रहे हैं। विवाह से कोई संतान नहीं है। दोनों पक्षों की ओर से क्रूरता और पलायन के तीखे आरोप हैं और पिछले 25 से अधिक वर्षों में दोनों के बीच कई मुकदमे हैं। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच यह कड़वा संबंध, जिसने पिछले 25 वर्षों से शांति का कोई क्षण नहीं देखा है, केवल कागज पर एक वैवाहिक संबंध है। तथ्य यह है कि यह रिश्ता अपरिवर्तनीय रूप से बहुत पहले टूट गया है।

11. उच्च न्यायालय ने यह विचार रखा है कि केवल अपीलार्थी-पति के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करना क्रूरता नहीं होगी। फिर भी, प्रत्यर्थी-पत्नी द्वारा अपीलार्थी-पति के खिलाफ दायर किए गए आपराधिक मामलों की संख्या बहुत अधिक है जिनकी ऊपर चर्चा की गई है। इन सभी मामलों के परिणामस्वरूप या तो अपीलार्थी-पति को आरोपमुक्त कर दिया गया है या बरी कर दिया गया है, यदि दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की घोषणा से पहले नहीं, लेकिन निश्चित रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की घोषणा के बाद। इसके अलावा, नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली 1 मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि वैवाहिक मामले में एक पक्ष द्वारा दूसरे के खिलाफ बार-बार आपराधिक मामले दर्ज करना क्रूरता के बराबर होगा और इसे इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने के. श्रीनिवास राव बनाम डी. ए. दीपा 2 मामले में दोहराया था।

12. एक अन्य पहलू जिस पर हमें विचार करना चाहिए, वह यह है कि पिछले 25 वर्षों से अपीलार्थी और प्रत्यर्थी अलग रह रहे हैं और साथ नहीं रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है। वास्तव में दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है और जैसा कि विधि आयोग ने अपनी 71 वीं रिपोर्ट में इस तरह के विवाह के बारे में कहा है, जो एक ऐसा विवाह है जो वास्तव में टूट गया है, और केवल कानून द्वारा न्यायिक मान्यता की आवश्यकता है। विधि आयोग ने अपनी 217 वीं रिपोर्ट में भी यही बात दोहराई थी।

13. इसी तरह की परिस्थितियों में, यह न्यायालय आर. श्रीनिवास कुमार बनाम आर. शमिता मामले में **3**, मुनीश कक्कड़ बनाम निधि कक्कड़ **4** और नेहा त्यागी बनाम लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक त्यागी **5** ने माना है कि एक अपरिवर्तनीय विवाह एक ऐसा विवाह है जहाँ पति और पत्नी रह रहे हैं और उनके फिर से एक साथ रहने की कोई संभावना नहीं है। उपरोक्त सभी तीन मामलों में, इस न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का

प्रयोग करते हुए अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर विवाह को भंग कर दिया है, जो अन्यथा हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मौजूद नहीं है। 14. नवीन कोहली (ऊपर) में, इस न्यायालय द्वारा भारत संघ को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के आधार के रूप में विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने को जोड़ने पर विचार करने के लिए एक मजबूत सिफारिश की गई है।

15. उनके बीच कई न्यायालयी लड़ाइयाँ और मध्यस्थता और सुलह में बार-बार विफलता कम से कम इस तथ्य की गवाही है कि अब दंपति के बीच कोई बंधन नहीं है, यह वास्तव में एक ऐसा विवाह है जो अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है।

16. अदालतों के समक्ष वैवाहिक मामले एक अलग चुनौती पेश करते हैं, किसी भी अन्य के विपरीत, क्योंकि हम मानवीय संबंधों को उसके सभी दोषों और कमजोरियों के साथ भावनाओं के बंडल के साथ निपट रहे हैं। हर मामले में जीवनसाथी के "क्रूरता" या निंदनीय आचरण की ओर इशारा करना संभव नहीं है। संबंधों की प्रकृति, एक-दूसरे के प्रति पक्षों का सामान्य व्यवहार, या दोनों के बीच लंबे समय तक अलगाव प्रासंगिक कारक हैं जिन्हें न्यायालय को ध्यान में रखना चाहिए। समर घोष बनाम जया घोष 6 में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने विस्तार से चर्चा की थी कि अधिनियम की धारा 13 (1) (आई. ए.) के तहत क्रूरता क्या होगी। उपरोक्त निर्णय में एक महत्वपूर्ण दिशानिर्देश क्रूरता का निर्धारण करने में न्यायालय के दृष्टिकोण पर है। यहां जिस बात की जांच की जानी चाहिए वह है संपूर्ण वैवाहिक संबंध, क्योंकि क्रूरता एक हिंसक कार्य या कृत्यों में नहीं हो सकती है, लेकिन किसी दिए गए मामले में हानिकारक निंदा, शिकायतों, आरोपों, ताने आदि से एकत्र किया जाना चाहिए। न्यायालय ने हैल्सबरी के लॉज ऑफ़ इंग्लैंड (खंड 13,4 वां संस्करण, पैरा 1269, पृष्ठ 602) में वैवाहिक संबंधों में क्रूरता की परिभाषा पर भरोसा किया, जिसे यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जाना चाहिए:

“क्रूरता के सभी मामलों में सामान्य नियम यह है कि पूरे वैवाहिक संबंध पर विचार किया जाना चाहिए, और यह नियम विशेष महत्व का है जब क्रूरता में हिंसक कृत्य नहीं बल्कि हानिकारक निंदा, शिकायत, आरोप या ताने शामिल होते हैं। ऐसे मामलों में जहां कोई हिंसा नहीं की जाती है, कुछ श्रेणियों को बनाने की दृष्टि से न्यायिक घोषणाओं पर विचार करना अवांछनीय है -

प्रकृति या गुण होने या न होने के रूप में कार्य या आचरण जो उन्हें क्रूरता के बराबर सभी परिस्थितियों में सक्षम या अक्षम बनाता है; क्योंकि यह क्रूरता की शिकायत का आकलन करने में अपनी प्रकृति के बजाय आचरण का प्रभाव है जो सर्वोपरि महत्व रखता है। क्या एक पति या पत्नी दूसरे के प्रति क्रूरता का दोषी रहा है, यह अनिवार्य रूप से तथ्य का सवाल है और पहले तय किए गए मामलों का बहुत कम, यदि कोई हो, मूल्य है। न्यायालय को पक्षकारों की शारीरिक और मानसिक स्थिति के साथ-साथ उनकी सामाजिक स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए, और एक पति या पत्नी के व्यक्तित्व और आचरण के दूसरे के मन पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करना चाहिए, उस दृष्टिकोण से पति या पत्नी के बीच सभी घटनाओं और झगड़ों पर विचार करना चाहिए; इसके अलावा, कथित आचरण की जांच शिकायतकर्ता की सहनशीलता की क्षमता और उस क्षमता के प्रकाश में की जानी चाहिए जिससे दूसरे पति या पत्नी को पता हो। क्रूरता के लिए दुर्भावनापूर्ण इरादा आवश्यक नहीं है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण तत्व है जहां यह मौजूद है।”

वर्तमान मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि पत्नी द्वारा केवल आपराधिक मामले दायर करना क्रूरता नहीं है क्योंकि यह भी देखा जाना चाहिए कि जिन परिस्थितियों में मामले दायर किए गए थे, हम पूरी तरह से उपेक्षा नहीं करना चाहते हैं, वास्तव में कानून के शुद्ध प्रस्ताव के रूप में यह सही हो सकता है, लेकिन फिर हमें मामले के पूरे तथ्यों की बारीकी से जांच करनी चाहिए जो अब हमारे सामने हैं। जब हम उन तथ्यों को ध्यान में रखते हैं जो आज भी मौजूद हैं, तो हम आश्चर्य हैं कि इस विवाह को जारी रखने का मतलब क्रूरता जारी रखना होगा, जो अब दोनों एक-दूसरे को देते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह का अपरिवर्तनीय टूटना विवाह के विघटन का आधार नहीं हो सकता है, लेकिन क्रूरता है। विवाह को तलाक की डिक्री द्वारा भंग किया जा सकता है, अन्य बातों के साथ-साथ, इस आधार पर कि दूसरे पक्ष ने "विवाह के अनुष्ठान के बाद याची के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है"। 17. हमारी सुविचारित राय में, एक वैवाहिक संबंध जो पिछले कुछ वर्षों में केवल अधिक कड़वा और कटु हो गया है, दोनों पक्षों पर क्रूरता फैलाने के अलावा कुछ नहीं करता है। इस टूटी हुई शादी के अग्रभाग को जीवित रखना दोनों पक्षों के साथ अन्याय करना होगा। एक विवाह जो अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है, हमारी राय में दोनों पक्षों के लिए क्रूरता का संकेत देता है, क्योंकि इस तरह के रिश्ते में प्रत्येक पक्ष दूसरे के साथ क्रूरता का व्यवहार कर रहा है। इसलिए यह अधिनियम की धारा 13 (1) (आई. ए.) के तहत विवाह के विघटन का आधार है।

17. अधिनियम के तहत क्रूरता को परिभाषित नहीं किया गया है। फिर भी, जिस संदर्भ में इसका उपयोग किया गया है, जो एक विवाह के विघटन के लिए एक आधार के रूप में है, यह दिखाएगा कि इसे एक वैवाहिक संबंध में 'मानवीय आचरण' और 'व्यवहार' के रूप में देखा जाना चाहिए। समर घोष (ऊपर) के मामले में सुनवाई करते हुए इस न्यायालय ने राय दी कि क्रूरता शारीरिक के साथ-साथ मानसिक भी हो सकती है:-

“46... यदि यह भौतिक है, तो यह तथ्य और डिग्री का सवाल है। यदि यह मानसिक है, तो क्रूर व्यवहार की प्रकृति और फिर जीवनसाथी के मन पर इस तरह के व्यवहार के प्रभाव के बारे में जांच शुरू होनी चाहिए। क्या यह उचित आशंका पैदा करता है कि दूसरे के साथ रहना हानिकारक या हानिकारक होगा, अंततः, आचरण की प्रकृति और शिकायत करने वाले जीवनसाथी पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। क्रूरता अनजाने में भी हो सकती है:- ... इरादे की अनुपस्थिति से मामले में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर मानवीय मामलों में सामान्य अर्थों में, जिस कार्य की शिकायत की गई है, उसे अन्यथा क्रूरता माना जा सकता है। क्रूरता में इरादा एक आवश्यक तत्व नहीं है। पार्टी को इस आधार पर राहत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जानबूझकर या जानबूझकर कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया है।”

हालाँकि इस न्यायालय ने अंततः मानसिक क्रूरता के कुछ उदाहरण दिए। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

(i) पक्षों के पूर्ण वैवाहिक जीवन पर विचार करने पर, तीव्र मानसिक पीड़ा, पीड़ा और पीड़ा जो पक्षों के लिए एक-दूसरे के साथ रहना संभव नहीं बनाती है, मानसिक क्रूरता के व्यापक मानकों के भीतर आ सकती है।

(xii) बिना किसी शारीरिक अक्षमता या वैध कारण के काफी समय तक संभोग करने से इनकार करने का एकतरफा निर्णय मानसिक क्रूरता के बराबर हो सकता है।

(xiii) विवाह के बाद पति या पत्नी में से किसी का भी विवाह से संतान न होने का एकतरफा निर्णय क्रूरता के समान हो सकता है।

(xiv) जहां निरंतर अलगाव की एक लंबी अवधि रही है, यह उचित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वैवाहिक बंधन सुधार से परे है। विवाह एक काल्पनिक बात बन जाती है, हालांकि एक कानूनी बंधन द्वारा समर्थित है। उस बंधन को तोड़ने से इनकार करने से, ऐसे मामलों में कानून, विवाह की पवित्रता की सेवा नहीं करता है; इसके विपरीत, यह पक्षों की भावनाओं और भावनाओं के लिए बहुत कम सम्मान दिखाता है। ऐसी स्थितियों में, यह मानसिक क्रूरता का कारण बन सकता है।

(जोर दिया गया)

18. हमारे पास एक विवाहित जोड़ा है जो मुश्किल से चार साल से एक जोड़े के रूप में एक साथ रहा है और जो अब पिछले 25 वर्षों से अलग रह रहे हैं। विवाह से कोई संतान नहीं है। वैवाहिक बंधन पूरी तरह से टूट गया है और सुधार से परे है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह संबंध समाप्त होना चाहिए क्योंकि इसकी निरंतरता दोनों पक्षों में क्रूरता का कारण बन रही है। लंबे समय तक अलग रहने और सहवास की अनुपस्थिति और सभी सार्थक बंधनों के पूरी तरह से टूटने और दोनों के बीच मौजूदा कड़वाहट को 1955 के अधिनियम की धारा 13 (1) (आई. ए.) के तहत क्रूरता के रूप में देखा जाना चाहिए। इसलिए हमारा मानना ​​है कि किसी दिए गए मामले में, जैसे कि एक मामले में, जहां वैवाहिक संबंध अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है, जहां पक्षों के बीच कई न्यायालयी मामलों के साथ लंबे समय तक अलगाव और सहवास का अभाव है (जैसा कि पिछले 25 वर्षों से वर्तमान मामले में है), तो इस तरह के 'विवाह' को जारी रखने का मतलब केवल क्रूरता को मंजूरी देना होगा जो प्रत्येक दूसरे पर डाल रहा है। हम इस तथ्य से भी अवगत हैं कि इस विवाह के विघटन से केवल दोनों पक्ष प्रभावित होंगे क्योंकि विवाह से कोई संतान नहीं है।

19. इन परिस्थितियों में, हम विचारण न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हैं, हालांकि हमारे आदेश में हमारे द्वारा दिए गए विभिन्न आधारों के लिए, और हम उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त करना चाहते हैं और अपीलार्थी/पति को तलाक की डिक्री देते हैं। उनकी शादी टूट जाएगी।

20. हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता/पति जीवन बीमा निगम में एक कर्मचारी है, जैसा कि हमें बार में सूचित किया गया है और उसका वर्तमान वेतन प्रति माह रुपये

से अधिक है-(एक लाख रुपये), हम इसे उचित और उचित मानते हैं कि वह प्रतिवादी/पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में <ID1,00,000/- (तीस लाख रुपये) की राशि देता है। Rs.30,00,000/- (तीस लाख रुपये) की यह राशि प्रत्यर्थी के नाम पर चार सप्ताह की अवधि के भीतर जमा की जाएगी। आज से इस न्यायालय की रजिस्ट्री के साथ तलाक की डिक्री ऐसी जमा राशि की तारीख से ही प्रभावी होगी। ऐसी जमा राशि की स्थिति में, रजिस्ट्री प्रत्यर्थी/पत्नी की साख को सत्यापित करने के बाद इस न्यायालय को आगे भेजे बिना प्रत्यर्थी/पत्नी को राशि वितरित करेगी।

उपरोक्त निर्देशों के साथ, अपील की अनुमति है।

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायक: आदिराज बाली, एलसीआरए)